अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 76 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	14801,29,00	19126,84,00	18721,78,12	-405,05,88
पूरक	Supplementary	4325,55,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				405,00,24
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1128,97,00	1966,90,00	1165,70,83	-801,19,17
पूरक	Supplementary	837,93,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				801,19,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6129.00	4741.89	4736.65	-5.24
पु.	R.	-1387.11			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	1435273.00			
पू.	S.	432555.00	1857521.76	1857521.36	-0.40
पु.	R.	-10306.24			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	38726.00			
			7820.91	7820.91	..
पु.	R.	-30905.09			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1.00			
			2099.20	2099.20	..
पु.	R.	2098.20			

(I) ₹66527.00 लाख का प्रावधान चार मामलों में मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹66525.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन – उद्योगों/कंपनियों को सहायता – सीबीजी–सीजीडी कनेक्टिंग पाइपलाइन अवसंरचना विकसित करने वाली इकाई (सीजीडी इकाई/सीबीजी उत्पादक) को वित्तीय सहायता" – ₹49725.00 लाख योजना दिशानिर्देशों के अनुसार बेंचमार्क हासिल न करने की वजह से लाभार्थियों को निधियां जारी न करने के कारण।

(I) Provision of ₹66527.00 lakhs remained wholly unutilized in four cases under Major Head "2802"; of these ₹66525.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) "Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Assistance to Industries/companies - Financial assistance to entity (CGD entity/CBG Producers) developing CBG - CGD connecting pipeline infrastructure" - ₹49725.00 lakhs - due to non-release of funds to beneficiaries owing to non-achievement of benchmark as per scheme guidelines.

(खा) "सामान्य – स्वायत्त निकायों को सहायता – भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम की स्थापना" – ₹16800.00 लाख परियोजना की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।

(B) "General - Assistance to Autonomous Bodies - Setting up of Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE), Vishakhapatnam" - ₹16800.00 lakhs - due to non-receipt of approval for extension of timeline of the project.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1392.35 लाख की बचत (₹6129.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्श के लिए प्रस्ताव हेतु आवेदन के आवंटन को अंतिम रूप न देने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Petroleum and Natural Gas" - saving of ₹1392.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6129.00 lakhs) was due to non-finalisation of awards of Request for Proposal for consultancy and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2802" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2802" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन – उद्योगों/कंपनियों को सहायता – बायोमास के संग्रह के लिए सीबीजी उत्पादकों को वित्तीय सहायता" – ₹14828.10 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार बेंचमार्क हासिल न होने की वजह से लाभार्थियों को धनराशि जारी न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Assistance to Industries/companies - Financial assistance to CBG producers for collection of Biomass" - saving of ₹14828.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-release of funds to beneficiaries owing to non-achievement of benchmark as per scheme guidelines.

(खा) "तेल और गैस का शोधन और विपणन" –

(B) "Refining and Marketing of Oil and Gas" -

(क) "तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जी–वन योजना" – ₹10983.50 लाख की बचत (₹11741.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा निधियों के वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण हुई।

(a) "Marketing of Oil - Pradhan Mantri JI - VAN Yojana" - saving of ₹10983.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11741.00 lakhs) was due to non-achievement of milestones by Hindustan Petroleum Corporation Limited for disbursement of funds.

(ख) "प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की स्थापना – इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) – उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा" – ₹38808.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग अधिकार (आरओयू) के मुद्दों और

(b) "Setting up of Natural Gas Pipe Line - Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) - Part of the North East Natural Gas Pipeline Grid" - saving of ₹38808.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to slowing down of

मानसून की वजह से निर्माण गतिविधियों में मंदी के कारण हुई।

construction activities owing to Right of Use (RoU) issues and monsoon.

(गा) "सामान्य" –

(C) "General" -

(क) "तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी" –

(a) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(i) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹98301.78 लाख की बचत (₹131100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तेल विपणन कंपनियों से कम बिलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) "DBT for LPG" - saving of ₹98301.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹131100.00 lakhs) was due to receipt of less bills from Oil Marketing Companies.

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (घरेलू प्राकृतिक गैस) सहित देय अन्य सब्सिडी" – ₹8414.20 लाख की बचत (₹104880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में एपीएम गैस की बिक्री पर सब्सिडी के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)" - saving of ₹8414.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹104880.00 lakhs) was due to receipt of less bills from Oil and Natural Gas Corporation and Oil India Ltd. towards subsidy on sale of APM gas in the North-Eastern Region.

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता – भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) (ओएंडएम) को भुगतान" – ₹12004.38 लाख की बचतें (₹22004.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय सामरिक रिजर्व लिमिटेड में सॉवरेन क्रूड ऑयल बीमा प्रीमियम को शामिल न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Autonomous Bodies - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) (O&M)" - savings of ₹12004.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22004.00 lakhs) was due to non-inclusion of Sovereign Crude Oil insurance premium at ISPRL and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (घरेलू प्राकृतिक गैस) सहित देय अन्य सब्सिडी" – ₹799.06 लाख की बचत (₹9960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में एपीएम गैस की बिक्री पर सब्सिडी के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और ऑयल इंडिया

(i) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)" - saving of ₹799.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9960.00 lakhs) was due to receipt of less bills from Oil and Natural Gas Corporation

लिमिटेड से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹9335.29 लाख की बचत (₹12450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹4836.36 लाख की बचत (₹6450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरी उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग – भारत में पीएनजी के लिए व्यापारी जहाजों का आरंभ" के अंतर्गत ₹30905.09 लाख की बचत (₹38726.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत तेल विपणन कंपनियों से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹254945.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2802" – "सामान्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2025 में ₹310000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) "तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी" –

(क) "गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन योजना (पीएमयूवाई)" – ₹208051.34 लाख।

(ख) "बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीडस्टॉक सब्सिडी" – ₹16900.00 लाख।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन योजना (पीएमयूवाई)" – ₹19757.73 लाख।

and Oil India Ltd. towards subsidy on sale of APM gas in the North-Eastern Region.

(ii) "DBT for LPG" - saving of ₹9335.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12450.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub-Plan - DBT for LPG" - saving of ₹4836.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6450.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Flagging of Merchant Ships for PNG in India" - saving of ₹30905.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38726.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less bills from Oil Marketing Companies

2.(I) The above savings were partly (₹254945.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹310000.00 lakhs in March, 2025 under Major Head "2802" - "General" - under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(a) "Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹208051.34 lakhs.

(b) "Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Cracker Complex" - ₹16900.00 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹19757.73 lakhs.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन योजना (पीएमयूवाई)" – ₹10235.93 लाख।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Scheme for LPG connection to Poor Households (PMUY)" - ₹10235.93 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – राज्य सरकारों को अंतर रॉयल्टी का भुगतान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹2098.20 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाइड्रोजन महानिदेशालय से बढ़े हुए अनुमानों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Payment of Differential Royalty to State Governments" - excess of ₹2098.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to receipt of increased estimates from Directorate General of Hydrocarbons.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹80119.17 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त ₹83793.00 लाख के पूरक अनुदान का 96 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall saving (₹80119.17 lakhs) constituted 96 percent of supplementary grants of ₹83793.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 41 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4802"	Major Head "4802"				
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	112802.00			
पू.	S.	83791.00	100515.57	100515.57	..
पु.	R.	-96077.43			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	95.00			
पू.	S.	2.00	16055.26	16055.26	..
पु.	R.	15958.26			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4802" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4802" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन – अनुसंधान / अनुसंधान विकास" –

(A) "Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Research/Research Development" -

(क) "मिशन अन्वेषण" – ₹28200.00 लाख की बचत (₹33200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Mission Anveshan" - savings of ₹28200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33200.00 lakhs); and

(ख) "भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ में क्षेत्रों का मूल्यांकन" – ₹33800.00 लाख की बचत (₹38800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Appraisal of Areas in India's Extended Continental Shelf" - savings of ₹33800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत अन्वेषण गतिविधियों के लिए निविदाएं प्रदान करने में विलंब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in award of tenders for exploration activities.

(खा) "कच्चे तेल का सावरेन रणनीतिक भंडारण – सावरेन रणनीतिक कच्चे तेल रिजर्व का निर्माण – भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान" – ₹39075.00 लाख की बचत (₹40800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैवर्न के लिए भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL)" - saving of ₹39075.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40800.00 lakhs) was due to non-finalisation of acquisition of land for caverns.

4.(I) उपर्युक्त बचत (₹15958.26 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "5475" – "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद का पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (₹15958.26 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs under Major Head "5475" - "Direction and Administration - Secretariat - Economic Services".

(II) बचत मुख्य शीर्ष "4802" – "कच्चे तेल का सावरेन रणनीतिक भंडारण – सावरेन रणनीतिक कच्चे तेल रिजर्व का निर्माण – चरण–I रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का विस्तार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹4999.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4802" - "Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve - Extension of Phase-I Strategic Petroleum Reserves" - excess of ₹4999.00 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) आईएसपीआरएल चरण–I विस्तार के लिए भूमि को अंतिम रूप देने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards finalization of land for ISPRL Phase-I Extension.

5. *तेल उद्योग विकास निधिः–*

इस निधि का गठन भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तेल कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विकास के लिए तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 47) के तहत की गई थी। निधि का वित्तपोषण विनिर्दिष्ट मदों पर उत्पाद शुल्क के भाग के रूप में कच्चे तेल पर उपकर के शुल्क द्वारा किया गया था। यद्यपि अधिनियम की धारा 16 में शुल्क से आय को भारत की समेकित निधि में जमा कराने का प्रावधान है, धारा 17 में केंद्र सरकार इस संबंध में संसद में पारित कानून द्वारा उचित विनियोग के बाद, ऐसी धनराशि, जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझती है, अधिनियम के प्रयोजनार्थ अंतरण कर सकती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 18 में तेल उद्योग विकास निधि सृजित करने का प्रावधान है जिससे धारा 16 या धारा 17 के अंतर्गत संग्रहित राशि उसमें उल्लिखित प्रयोजनार्थ जमा और प्रयोग की जानी चाहिए।

5. ***Oil Industry Development Fund:-***

The fund was constituted under the Oil Industry Development Act, 1974 (Act No.47 of 1974) for the development of the Oil Industry/PSUs under the control of Govt. of India. The fund was financed by the levy of cess on Crude Oil as part of excise duty on the items specified therein. While Section 16 of the Act Provides for crediting of proceeds of duty to Consolidated Fund of India, Section 17 provides that the central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, transfer such sums of money as the Central Government may consider necessary for the purpose of the Act. Section 18 of the Act further provides for the creation of Oil Industry Development Fund (OIDF) wherein the money collected under Section 16 or section 17 shall be credited and applies for the purposes defined therein.

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा निम्नानुसार थाः–

The Account of the fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipt	3130,00,00
अदायगियां	Payments	2117,25,00
अंतशेष	Closing Balance	1012,75,00